

सम्पादकीय

भारत पर दबाव की नीति से काम कर रहे हैं, बयानों में देखने को मिले कई उत्तर-चढ़ाव

भारत ने हाल के वर्षों में अपने निर्वाचन के पक्ष को जिस तरह मजबूत किया है, उसमें इस तरह के अमेरिकी दबाव का व्यापार में सहयोग के बजाय एक प्रतिरक्षित की बिलास किया जाना नहीं है? पिछले कुछ समय से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह अलग-अलग दर्शों पर शुल्क लगाने की बात कर रहे थे, उसे कई अर्थों में दबाव की रणनीति माना जा रहा था। इस मसले पर अब उन्होंने जिस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिया है, उससे साफ़ है कि मनवाने तरीके से शुल्क लगाने के फैसले का इसमाल किसी देश की नीति को प्रभावित करने के लिए एक और ज़रूरी के तौर पर किया जा रहा है। इस क्रम में ट्रंप बीते दिनों बार-बार यह कहते हैं कि वे भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाएंगे। भारत उनके बयानों में जैसे उत्तर-चढ़ाव देखे गए, उसके महेनजर यह उम्मीद की जा रही थी कि वे अपनी जिद पर विचार करेंगे और भारत को लेकर उदार रुख अपनाएंगे। खासतौर पर इसलिए भी कि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के नए दरवाजे खुले थे और योंगु संवित्राता बढ़ी थी। गोलतलब है कि व्यापार वार्ता के संदर्भ में अमेरिका और भारत के बीच जारी बातचीजों में कुछ गतिरोध के संकेत सामने आये हैं जो बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात की जाने वाली रस्तुओं पर एक असर से पक्षीय फैसले शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का फैसला कोई आचानक नहीं हालांकि वह कोई आचानक हुआ फैसला नहीं लगाता है और ट्रंप ने इस बार समझौते में अपने के बाद रुक्ख लगाने की घोषणा और प्रकृत जगहों पर अमल करना शुल्क कर दिया है। मसलेन, कनाडा पर ट्रंप ने पैकेट्स फैसले शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी, जबकि उस समय व्यापार वार्ता के साथ द्विपक्षीय अंतर्रिम व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की कोशिशें जारी थीं। निर्वाचन आयोग की ओर से तय किए गए नारायणका प्रमाण पत्र को लेकर सबसे बड़ा विवाद उल्लेखनीय है कि अमेरिका के बातकारों का एक समृद्ध पच्चीस असर को भारत के दौरे पर आयोग की जाने वाली है जो प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीज के अगले दौर में हिस्सा लेगा। सबाल है कि व्यापार वार्ता के प्रयास जारी रहने और उसके निकर्ष तक पहुंचने से पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति को शुल्क लगाने की घोषणा करने की जल्दबाजी करने की जरूरत क्यों लगी? क्या इस फैसले को व्यापार वार्ता में अपने हित में नीतिगत फैसले लेने के लिए दबाव बनाने की रणनीति नहीं माना जाएगा? ट्रंप की ताजा घोषणा से कुछ अन्य देशों के मुकाबले भारत पर कम असर पड़ेगा एक दरील यह दी गई है।

आज का विचार

महेनत

वो सुनहरी चाबी है
जो बंद भविष्य के
दरवाजे भी खोल देती है

भारत संवाद



राशिफल

मेष राशि: कार्यक्षेत्र में आपको अपने छोटे-छोटे कारों को पूरा करने के लिए उन लोगों की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, जो आपके विरोध में खड़े रहते हैं। लेकिन अपर आप समझौती और चतुराइ से जो जाना बनाकर हर काम करते हैं।

वृषभ राशि: आपको कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों को कार्यालय पर एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं। इसी के चलते आपको प्रेरणा भी महसूस होगी।

गृह राशि: आपको कार्यक्षेत्र में एक साथ कई सारे काम करने पड़ सकते हैं। इसी के चलते आपको व्यापार वार्ता में अपने किसी जीवन पर जाना चाहिए। जीवन पर लंबे समय बाद आपको अपने काम को प्रेरणा भी महसूस होगी।

मध्य राशि: आपको कार्यक्षेत्र में काम करना पड़ सकता है। नौकरी करने वालों को साथ-साथ एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं। इसी के चलते आपको व्यापार वार्ता में अपने किसी जीवन पर जाना चाहिए। जीवन पर लंबे समय बाद आपको अपने काम को प्रेरणा भी महसूस होगी।

कर्त्तव्य राशि: आपको कार्यक्षेत्र में एक साथ कई सारे काम करने पड़ सकते हैं। इसी के चलते आप ज्यादा व्यस्त होंगे और भागदी हैं में रहेंगे।

व्यापार के मामले में आपको किसी जीवन पर जाना पड़ सकता है, जिसकी तैयारी करना भी ज़रूरी होगा। वहाँ, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के बातों को किसी अच्छे काम का उपरकरण हो सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

कर्त्तव्य राशि: आपको कार्यक्षेत्र में विवाद उत्तम होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आपको शान्त और संयुक्त रखना होगा। क्रांति-विवरण पर एक अधिकारीयों को बढ़ावा देने से अपनी कामों को समय पर पूरा कर सकते हैं।

मीन राशि: कार्यक्षेत्र में आपका दिन ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कोई भी फैसला सोचा-समझकर लेना बेहतर होगा। अगर आप कार्यालय पर अपने प्रोजेक्ट या ज़स्ती कारों को गंभीरता से पूरा कर सकते हैं, तो इससे उन्नति प्राप्त हो सकती है।

ज्योतिष सेवा केन्द्र ज्योतिषवार्य पंडित अतुल शास्त्री

अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का स्वदेशी पर जोर

प्रधानमंत्री ने कोविड

महामारी के समय
आत्मनिर्भर भारत
और स्वदेशी
उत्पादों की खरीद
पर जोर दिया था
लेकिन बात बनी
नहीं। स्वदेशी के मंत्र
को महत्व दिया
जाना चाहिए लेकिन
समस्या यह है कि
लोगों के समक्ष
पर्याप्त संख्या में सही
गुणवत्ता के स्वदेशी
उत्पाद उपलब्ध

नहीं हैं।

प्रधानमंत्री से टैरिफ विवाद और
विशेष रूप से

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में स्वदेशी की जो पक्षधरता की, वह सही तो है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वे स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील पहले भी कर चुके हैं और किन्तु कारोबारी के समय और भारत के लिए एक और ज़रूरी दबाव है। इस क्रम में ट्रंप बीते दिनों बार-बार यह कहते हैं कि वे भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाएंगे। भारत उनके बयानों में जैसे उत्तर-चढ़ाव देखे गए, उसके महेनजर यह उम्मीद की जा रही थी कि वे अपनी जिद पर विचार करेंगे और भारत को लेकर उदार रुख अपनाएंगे। खासतौर पर इसलिए भी कि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के नए दरवाजे खुले थे और योंगु संवित्राता होने की उम्मीद थी। गोलतलब है कि व्यापार वार्ता के संदर्भ में अमेरिका और भारत के बीच जारी बातचीजों में कुछ गतिरोध के संकेत सामने आये हैं जो बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात की जाने वाली रस्तुओं पर एक असर से पक्षीय फैसले शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का फैसला कोई आचानक नहीं हालांकि वह कोई आचानक हुआ फैसला नहीं लगाता है और ट्रंप ने इस बार समझौते में अपने के बाद रुक्ख लगाने की घोषणा और प्रकृत जगहों पर अमल करना शुल्क कर दिया है। मसलेन, कनाडा पर ट्रंप ने पैकेट्स फैसले शुल्क लगाने की घोषणा कर दी थी, जबकि उस समय व्यापार वार्ता के साथ द्विपक्षीय अंतर्रिम व्यापार समझौते को लेकर अंतिम दौर की कोशिशें जारी थीं। निर्वाचन आयोग की ओर से तय किए गए नारायणका प्रमाण पत्र को लेकर सबसे बड़ा विवाद उल्लेखनीय है कि अमेरिका के बातकारों का एक समृद्ध पच्चीस असर को भारत के दौरे पर आयोग की जाने वाली है जो प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीज के अगले दौर में हिस्सा लेगा। सबाल है कि व्यापार वार्ता के प्रयास जारी रहने और उसके निकर्ष तक पहुंचने से पहले ही अमेरिका राष्ट्रपति को शुल्क लगाने की घोषणा करने की जल्दबाजी करने की जरूरत क्यों लगी? क्या इस फैसले को व्यापार वार्ता में अपने हित में नीतिगत फैसले लेने के लिए दबाव बनाने की रणनीति नहीं माना जाएगा? ट्रंप की ताजा घोषणा से कुछ अन्य देशों के मुकाबले भारत पर कम असर पड़ेगा एक दरील यह दी गई है।

प्रधानमंत्री ने कोविड
महामारी के समय
आत्मनिर्भर भारत
और स्वदेशी
उत्पादों की खरीद
पर जोर दिया था
लेकिन बात बनी
नहीं। स्वदेशी के मंत्र
को महत्व दिया
जाना चाहिए लेकिन
समस्या यह है कि
लोगों के समक्ष
पर्याप्त संख्या में सही
गुणवत्ता के स्वदेशी
उत्पाद उपलब्ध

अनेक ऐसे उत्पाद पर्याप्त स्वदेशी का मंत्र उत्तर का अधिक प्रभावी नहीं, जितना नियंत्रित होनी दिया जाता है। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में स्वदेशी की जो पक्षधरता की, वह सही तो है, लेकिन यह ध्यान रहे कि वे स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील पहले भी कर चुके हैं और किन्तु कारोबारी के समय और भारत के लिए एक और ज़रूरी दबाव है। इस क्रम में ट्रंप बीते दिनों बार-बार यह कहते हैं कि वे भारत से आयात किए जाने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लगाएंगे। भारत उनके बयानों में जैसे उत्तर-चढ़ाव देखे गए, उसके महेनजर यह उम्मीद की जा रही थी कि वे अपनी जिद पर विचार करेंगे और भारत को लेकर उदार रुख अपनाएंगे। खासतौर पर इसलिए भी कि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के नए दरवाजे खुले

रूस के कामचटका में 600 साल बाद ज्वालामुखी फटा

6 किमी ऊंचाई तक राख का गुबार फैला; यहाँ दुनिया का छठा बड़ा भूकंप आया था

एजेंसी

मॉस्को, रूस के कामचटका में 600 साल बाद क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में पहली बार विस्फोट हुआ।

कामचटका के इमरजेंसी मंत्रालय ने रविवार को बताया कि 2 अगस्त को इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। मंत्रालय ने कहा- 1856 मीटर ऊंचे क्रशेनिनिकोव ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था।

के बाद 6 हजार मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार फैल गया। इसके चलते इस इलाके का एयर स्पेस बंद कर दिया गया।

वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विस्फोट का संबंध 4 दिन पहले रूस के कामचटका के इलाके में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से हो सकता है। इससे पहले बुधवार को कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित कल्याचेस्काया सोपका ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था।



सोपका ज्वालामुखी यूरोप और एशिया में सबसे एकिवक्त्वा ज्वालामुखी है। यह दोनों ज्वालामुखी भूकंप से दूनिया में हुए हैं, वह रिंग ऑफ फायर के पास मौजूद है। रिंग ऑफ फायर ऐसा इलाका है जहाँ कई कॉर्टेंटेंट के साथ ही ओशियनिक टेक्नोनिक प्लेट्स भी हैं। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है, सुनामी उठती है और ज्वालामुखी फटते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी

रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र 40 हजार किलोमीटर में फैला है। दुनिया में जिस सक्रिय ज्वालामुखी है, उनमें से 75% इसी क्षेत्र में हैं। 15 देश इस रिंग ऑफ फायर की जद में हैं। किंतने देशों में ही रिंग ऑफ फायर का असर जापान, रूस, फिलिपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली, बोलिविया।

जुलाई में कामचटका में 6 ताकतवर भूकंप आए

बुधवार का आया भूकंप दुनिया का छठा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसके बाद रूस, अमेरिका, जापान और चीली सेतु कई देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की थी। जापान ने अपने फुकिशिया परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया था और टोकोयो में करीब 20 लाख लोगों को घर खाली नहीं हुई थी।

खालिस्तान विरोधी एक्टिविस्ट की अमेरिका में मौत खालिस्तानी समर्थकों से धमकियां मिल रही थीं, पुलिस जांच में जुटी

एजेंसी



करते थे और 17 अगस्त को वाशिंगटन डीसी में होने वाले खालिस्तान रेस्टेंटम (जनमत संग्रह) का खुलकर विरोध कर रहे थे। 'द खालिसा टुडे' के संस्थापक और सीईओ सुखी को खालिस्तानी समर्थकों से लगातार धमकियां मिल रही थीं। फिर भी, वे

अपनी बात पर अडिग रहे। उनके परिचय बूटा सिंह कलेर ने कहा कि उनकी मौत से भारत समर्थक समुदाय में शोक की लहर है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सच समझे आएं। सुखी भारतीय प्रवासियों की अमेरिका के

कानूनों का पालन करने और अपराध से दूर रहने की सलाह देते थे। हाल ही में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, 'अमेरिका में कानून का पालन जरूरी है। अपराध करने पर वीजा रद्द हो सकता है और वापसी मुश्किल हो सकती है।' सुखी चहल का जन भारत के पंजाब के मानसा जिले में हुआ था। वे 1992 में अमेरिका चले गए। उन्होंने 1988 से 1992 तक लुधियाना के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की और पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड और यसी बिर्कले में कंप्यूटर और प्रबंधन से जुड़े विषयों को सीधे किए। सुखी ने सिलिकॉन वैली की कई कंपनियों में विशेषज्ञ रियरिंग किया, जिसमें खालिस्तानी संगठनों का जिक्र किया गया।

और सलाहकार के रूप में काम किया। वे 2015 से कैलिफोर्निया की बैन-लाइकरी संस्था पंजाब फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष थे, जो ग्रीब बच्चों को शिक्षा के लिए समर्थन देती है। चहल द खालिसा टुडे के संस्थापक और अध्यक्ष भी थे। सुखी सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थे और उन्होंने हिंदू, सिख और यहूदी समुदायों के बीच एकता बढ़ाने में अमृत भूमिका निभाई। द खालिसा टुडे के मुताबिक वे भारत के स्कॉलर और अमेरिकी जिसमें विशेषज्ञ रियरिंग के लिए जारी की गयी थी। उन्होंने 1992 तक रामनिंगिंग के गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की और पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड के लिए एक रिपोर्ट में भारत को 12 दमनकारी देशों की सूची में शामिल किया, जिसमें खालिस्तानी संगठनों का जिक्र किया गया।

इजराइली मंत्री ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद, यहाँ यहूदी करने पर रोक दिया। एजेंसी

तेल अबीव, इजराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गिर ने रविवार को यद्दशलम में अल-अक्सा मस्जिद के कैपस में जाकर प्रार्थना की। एक यहूदी संगठन ने इसका बीड़ियों जारी किया, जिसमें विशेषज्ञ कुछ लोगों के साथ मस्जिद के कैपस में यहूदी और प्रार्थना करते नजर आए। मवका और मदीना के बाद अल-अक्सा मस्जिद की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। नियमों के मुताबिक, यहूदी लोग यहाँ जा सकते हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। सोलान भीड़िया पर विवाद बढ़ाता देख इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहु ने कहा कि ये नियम नहीं बदले हैं और न ही बदलें। बेन-गिर का यह दौरा 'तिरावां बाव' के दिन हुआ, इस दिन यहूदी लोग उपचान करते हैं। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने याजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दी है। इसके बावजूद वे तेवाह के बावजूद यहूदी लोग वहाँ जाते हैं। जारी की गयी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर आने की अनिवार्यता है। बेन-गिर ने कहा कि उन्होंने याजा में बहास के खिलाफ इजराइल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्र

